◆ ADVT ◆
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

NEED24 NEWS
हर ख़बर, हर शहर

नीड 24 न्यूज़

हर खबर, हर शहर

◆ ADVT ◆
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION
UNDER PROCESS
Application No.
T/GJ/2026/0619/2304/1577

GST
GSTIN
24CINPG0564Q1ZT

UDYAM REGISTERED
UDYAM-GJ-14-0003714

◆ DIGITAL NEWS NETWORK ◆
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.need24.digital
info@need24.in
+91 98700 06472
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

नौकरी

हिमाचल में सरकारी पदों की हजारों रिक्तियां



हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया कि विभिन्न विभागों में हजारों सरकारी पद अभी भी खाली हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये रिक्तियां प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

अधिकारी योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, क्योंकि सरकार जल्द ही कई भर्ती अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इन पदों में क्लर्क, इंजीनियर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विविध कार्य शामिल हैं।

पदों की भरपाई में देरी के कारण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट आई है, इसलिए सरकार ने चयन प्रक्रिया को तेज करने और आगामी महीनों में अतिरिक्त परीक्षा आयोजित करने का वचन दिया है।

यह जानकारी स्थानीय समाचार साइट जीवंतुशा द्वारा प्रकाशित की गई है, जो नौकरी चाहने वालों को राज्य की रोजगार वेबसाइट पर अपडेट और आवेदन की अंतिम तिथियों की निगरानी करने की सलाह देती है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 माप का भूकंप

एशियनएट न्यूज़ेबल के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 माप का हल्का भूकंप दर्ज किया गया। यह हल्का भूकंप सतही स्तर पर हुआ और आज के दिन क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया पहला उल्लेखनीय भूकंपीय घटना है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि 2.8 की तीव्रता सामान्यतः मामूली मानी जाती है और अक्सर केवल निकटवर्त

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 तीव्रता का भूकंप

संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वे (USGS) ने मंगलवार को 04:12 GMT पर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 2.8 तीव्रता का उथला भूकंप दर्ज किया। यह हल्का झटका आसपास के कस्बों में महसूस किया गया, परन्तु कोई क्षति या चोटें रिपोर्ट नहीं हुईं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि की कि इस भूकंप से कोई भू-स्खलन या

नौकरी

उना RTA मीटिंग के लिए आवेदन 26 नवंबर तक, मीटिंग 2 दिसंबर को



हिमाचल प्रदेश के उना जिले की रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ने 2 दिसंबर को मीटिंग आयोजित करने की घोषणा की है। इच्छुक प्रतिभागियों को 26 नवंबर तक अपना आवेदन जमा करना अनिवार्य है, जैसा कि जीवनउत्साह न्यूज़ पोर्टल पर बताया गया है।

नोटिस में मीटिंग के एजेंडा का उल्लेख नहीं है, परन्तु पंजीकरण की सीमित अवधि से यह स्पष्ट है कि अधिकारी, हितधारक और जनता को उपस्थित रहने के लिए समय पर आवेदन करना होगा।

आवेदकों को वेबसाइट पर दी गई निर्देशावली का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज़ समय सीमा से पहले अपलोड करने की सलाह दी जाती है, ताकि अयोग्यता से बचा जा सके।

आगे की जानकारी, जिसमें स्थल और समय शामिल है, आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद सफल पंजीकरणकर्ताओं को सूचित की जाएगी।

स्वास्थ्य

हिमाचल के सीएम ने शहपुर में सिविल अस्पताल की नई इमारत का उद्घाटन किया



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने आज शहपुर सिविल अस्पताल में नई इमारत का उद्घाटन किया। इस विस्तार से ग्रामीण इलाकों के रोगियों के लिए अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस आधुनिक सुविधा में उन्नत वार्ड, डायग्नोस्टिक सेंटर और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था शामिल है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नई इमारत से नजदीकी अस्पतालों पर रोगियों का दबाव कम होगा और आवश्यक सेवाओं तक तेज़ पहुँच संभव होगी।

स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर उपस्थित होकर आशावाद व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि अस्पताल के नवीनीकरण से स्वास्थ्य देखभाल में मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। यह उद्घाटन क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के सरकार के संकल्प का एक महत्वपूर्ण कदम है।

टेक्नोलॉजी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एआई सामग्री और जालसाजी में कानूनी अंतर निर्धारित किया

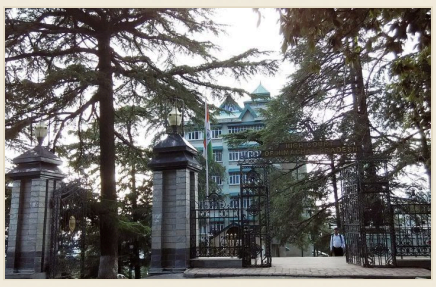

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एआई-आधारित सामग्री के उपयोग से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए एक निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि एआई द्वारा निर्मित पाठ या चित्र स्वचालित रूप से जालसाजी नहीं माने जाएंगे, जब तक कि धोखा देने का इरादा स्पष्ट न हो।

जालसाजी के लिए भारतीय कानून में जानबूझकर झूठी सामग्री बनाकर किसी तीसरे पक्ष को भ्रमित करने का इरादा आवश्यक है। एआई उपकरण केवल इनपुट डेटा के आधार पर आउटपुट उत्पन्न करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी उपयोगकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करती है, न कि तकनीक पर।

वकीलों और प्रवर्तन एजेंसियों को एआई-सहायता प्राप्त दस्तावेजों के मामलों में इस अंतर को लागू करने का निर्देश दिया गया, ताकि वास्तविक आपराधिक कृत्य को तकनीकी उपयोग के साथ मिलाकर न देखा जाए।

यह निर्णय भविष्य में एआई-जनित सामग्री और आपराधिक कानून के टकराव वाले विवादों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जिससे न्यायपालिका तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठा सके।

बिज़नेस

भारत ने नया औद्योगिक अधिनियम मंजूर किया, HP उद्योगों में 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य



नवीनतम संसद सत्र में नया औद्योगिक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत उच्च-प्रदर्शन (HP) उद्योगों में 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य किया गया।

इस कानून के अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और उच्च-मूल्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों को अपने कार्यबल का कम से कम 80% भारतीय नागरिकों से बनाना अनिवार्य है। यह कदम विदेशी कुशल श्रम पर निर्भरता घटाने और घरेलू रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कानून में अनुपालन तंत्र भी निर्धारित किया गया है, जिसमें कंपनियों को वार्षिक कार्यबल रिपोर्ट श्रम व रोजगार मंत्रालय को जमा करनी होगी। निर्धारित कोटा न पूरा करने पर दंड और उससे अधिक करने पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यह नीति स्थानीय भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है, विशेषकर उभरते प्रौद्योगिकी केंद्रों में, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिभा अधिग्रहण रणनीतियों को पुनः आकार दे सकती है।

विदेश

लाहौर कॉलेज के गुब्बारे हिमाचल की छत पर पहुँचे, पुलिस ने शुरू की जाँच



लाहौर, पाकिस्तान के एक कॉलेज समारोह में छोड़े गए गुब्बारे हवा के साथ बहकर भारत के हिमाचल प्रदेश में एक आवासीय छत पर पहुँचे। स्थानीय निवासियों ने इन विदेशी वस्तुओं को छत पर गिरते देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया।

हिमाचल पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारी गवाहों से बयान ले रहे हैं और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि गुब्बारे कैसे सीमा पार हुए।

जांच के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि अब तक कोई क्षति या चोट नहीं हुई है, परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। एजेंसियां पिछले समान घटनाओं की जाँच भी कर रही हैं और भविष्य में ऐसी अनजानी प्रवेश को रोकने के उपाय तलाश रही हैं।

यह घटना पहाड़ी सीमा क्षेत्रों में कम ऊँचाई वाले हवाई वस्तुओं की निगरानी की कठिनाइयों को उजागर करती है, जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच बेहतर निगरानी और स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने विधायक राजीव जासरोटिया के पिता को श्रद्धांजलि दी



हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने विधायक राजीव जासरोटिया के पिता को श्रद्धांजलि दी। यह सम्मान एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान दिया गया, जिससे गवर्नर की परिवार के प्रति संवेदना स्पष्ट हुई। दैनिक एक्सेल्सियर ने इस कार्यक्रम को कवर किया, जिसमें गवर्नर की उपस्थिति को शोक व्यक्त करने के एक प्रतीक के रूप में बताया गया।

रिपोर्ट में स्थान या श्रद्धांजलि के स्वरूप के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। गवर्नर का यह कदम सार्वजनिक प्रतिनिधियों के परिवारों को सम्मानित करने की परम्परागत प्रथा के अनुरूप है।

विधानसभा सदस्य राजीव जासरोटिया ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की, और रिपोर्ट ने केवल गवर्नर के इस कृत्य पर प्रकाश डाला।

सरकारी योजना

हिमाचल प्रदेश ने खेल योजना का बजट दो वर्ष के लिए रोका



हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी राज्य खेल योजना के लिए बजट को दो वर्ष के लिए रोकने का निर्णय लिया है, जिससे खेल बुनियादी ढांचे और एथलीट विकास कार्यक्रमों के लिए फंडिंग पर असर पड़ेगा।

यह निर्णय नवीनतम वित्तीय योजना सत्र के दौरान लिया गया, जिसके तहत अगले 24 महीनों के लिए योजना को कोई धनराशि नहीं मिलेगी, जिससे क्लब, प्रशिक्षण केंद्र और आगामी खेल आयोजनों पर असर पड़ेगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह रोक राज्य के व्यय की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है, हालांकि कटौती के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया।

खेल समुदाय के हितधारकों ने चिंता जताई है कि इस अवरोध से परियोजनाएँ विलंबित होंगी और स्थानीय एथलीटों के लिए अवसर सीमित होंगे।

राज्य समीक्षा पूर्ण होने और संशोधित बजट अनुमोदित होने पर फंडिंग फिर से शुरू करेगा।

देश

हिमाचल में खुले में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना



खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य इस समस्या से निपटने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना है। जुर्माना राशि और कार्यान्वयन प्रक्रिया के बारे में जल्द ही अधिक जानकारी जारी की जाएगी। सरकार उम्मीद करती है कि ये जुर्माने लोग गलत तरीके से कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करेंगे और स्थायी कचरा निपटान पद्धति अपनाएंगे।

हिमाचल में नया औद्योगिक अधिनियम: 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य



हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया औद्योगिक अधिनियम लागू किया है जिसमें राज्य में संचालित सभी उद्योगों को कम से कम 80% स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देना अनिवार्य है। यह हाल ही में पारित विधान राज्य के स्थानीय निवासियों की आर्थिक भलाई को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है, जो राज्य के भीतर अधिक नौकरी के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखता है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आबादी में बेरोजगारी कम होगी। इस नए अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रवर्तन से संबंधित विवरण राज्य सरकार द्वारा जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

राजनीति

हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में स्थायी हाई कोर्ट बेंच की मंजूरी दी



हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एक हालिया सत्र में विधायकों ने धर्मशाला में हिमाचल हाई कोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह कदम उत्तर क्षेत्रों के नागरिकों को उच्च न्यायालय की सेवाएँ निकट लाने के उद्देश्य से लिया गया है, जहाँ अब तक अधिकांश मामलों के लिए शिमला जाना पड़ता था।

विधायकों ने बताया कि स्थानीय बेंच से मुकदमों की लंबी लिस्ट घटेगी और वकीलों व पक्षकारों को यात्रा एवं खर्च में बचत होगी। प्रस्ताव में बेंच के संचालन के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की व्यवस्था करने का भी उल्लेख है।

राज्य सरकार को अब विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बजट आवंटन और न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल होगी। सफल कार्यान्वयन पर धर्मशाला बेंच राज्य की राजधानी के बाहर पहली स्थायी हाई कोर्ट शाखा बन जाएगी, जो न्यायिक पहुंच को विकेंद्रीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नौकरी

हिमाचल प्रदेश ने उद्योगों में 80% स्थानीय रोजगार के लिए विधेयक पारित किया



हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक नया रोजगार विधेयक पारित किया, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को अपने कार्यबल का कम से कम 80 प्रतिशत राज्य के निवासियों को देना अनिवार्य किया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रवास को रोकना और औद्योगिक विकास के लाभ स्थानीय जनसंख्या तक पहुँचाना है।

विधेयक में एकल-विंडो क्लियरेंस प्रणाली भी शामिल है, जिससे नई परियोजनाओं और विस्तार के लिए सभी अनुमोदन एक ही प्राधिकरण के माध्यम से शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक एक ही जगह पर सभी दस्तावेज़ जमा करेंगे, और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके प्रक्रिया तेज़ होगी।

चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, और अनुपालन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल गठित किया गया है। स्थानीय रोजगार लक्ष्य पूरा न करने वाली कंपनियों पर दंड या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

व्यवसाय संगठनों को 30 दिन की परामर्श अवधि के दौरान अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है, जिसके बाद विधेयक को अधिनियमित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह नीति हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी रोजगार संभावनाएँ पैदा करेगी, साथ ही निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखेगी।

बिज़नेस

KLK Ventures ने हिमाचल प्रदेश में 500 kW सौर परियोजना पर कब्जा किया

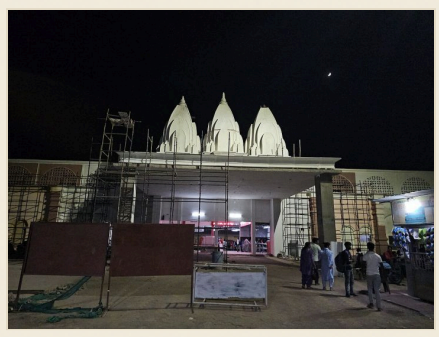

KLK Ventures, एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी, ने हिमाचल प्रदेश में 500 kW सौर परियोजना पर कब्जा किया है, जैसा कि Solarbytes ने बताया। यह परियोजना राज्य के स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। यह स्थापना KLK के उत्तरी भारत में बढ़ते उपस्थिति में योगदान देगी और स्थानीय नवीकरणीय पहलों का समर्थन करेगी। कंपनी ने कहा कि यह परियोजना उसके सतत ऊर्जा समाधान देने की रणनीति के अनुरूप है।

टेक्नोलॉजी

हिमाचल के सीएम ने कांगड़ा में 18.29 करोड़ रुपये का एसटीपीआई केंद्र खोला



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने कांगड़ा जिले में सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। लगभग 18.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह केंद्र प्रदेश में तकनीकी-उन्मुख उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को बुनियादी ढाँचा व समर्थन सेवाएँ प्रदान करेगा।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि इस केंद्र में इन्क्यूबेशन स्पेस, हाई-स्पीड इंटरनेट और परीक्षण प्रयोगशालाएँ होंगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच मिलेगी। यह परियोजना पर्यटन और कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था को विविधता देने के राज्य के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और स्थानीय मान्यताओं ने भाग लिया, जिन्होंने रोजगार सृजन और कौशल विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। एसटीपीआई केंद्र को प्रदेश में सॉफ़्टवेयर विकास, डिजिटल सेवाएँ और नवाचार का हब बनने की उम्मीद है।

केंद्र के अगले कुछ हफ्तों में संचालन शुरू होने की संभावना है, और पहली स्टार्ट-अप बैच 2027 की शुरुआत में यहाँ स्थापित होने की योजना है।

हिमाचल में मां नागरकोटी मंदिर में 150 साल पुराना पशु बलि का प्रथा समाप्त

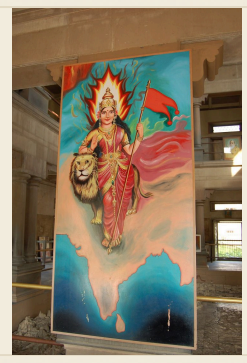

हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल, मां नागरकोटी मंदिर ने पशु बलि की पुरानी परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह प्रथा 150 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन हाल ही में मंदिर अधिकारियों द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। यह मंदिर अपनी मनोरम स्थिति के लिए जाना जाता है और हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है।

नौकरी

हिमाचल प्रदेश पटवारी 2026 एडमिट कार्ड जारी



हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने आज घोषणा की कि 2026 पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड अब उपलब्ध हैं। यह सूचना राज्य की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, जहाँ पात्र उम्मीदवार अपने पंजीकरण विवरण से लॉगिन करके कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एडमिट कार्ड पर अपना नाम, फोटो और रोल नंबर जैसी सभी जानकारी को परीक्षा के दिन से पहले ठीक से जांच लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में नियामक प्राधिकरण को निर्देशानुसार सूचित किया जाना चाहिए।

एडमिट कार्ड जारी होना पटवारी पदों के चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है, जो राज्य में भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर मूल एडमिट कार्ड के साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र ले जाने की याद दिलाई जाती है।

परीक्षा स्थल, समय और नियमों से संबंधित अतिरिक्त निर्देश उसी पोर्टल और आधिकारिक नोटिसों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

देश

हिमाचल प्रदेश में बदले नियमों के बाद पहली गांजा लाइसेंस जारी



हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में गांजे के औषधीय उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहली दो गांजा खेती लाइसेंस जारी किए हैं। यह कदम राज्य में गांजे के नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के बाद आया है, जिससे क्षेत्र में एक विनियमित गांजा उद्योग स्थापित होने की संभावना है। लाइसेंस आवेदकों के अनुभव, बुनियादी ढाँचे और प्रस्तावित खेती विधियों का मूल्यांकन करने के बाद जारी किए गए थे। इस विकास से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक अवसर पैदा होने और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य सरकार जिम्मेदार गांजा खेती को बढ़ावा देने और कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

हाई कोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की मातृत्व अवकाश की अनुमति दी



दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि दो या अधिक बच्चों वाली महिलाएँ अपने तीसरे बच्चे के लिए बारह हफ्ते का मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के हकदार हैं। यह आदेश मौजूदा श्रम कानूनों की व्याख्या करता है, जिससे पहले दो गर्भधारण पर लागू रहने वाले अवकाश को तीसरे बच्चे तक बढ़ाया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की मातृत्व सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है और उन कार्यरत माताओं की खाई को पाटता है, जिन्हें तीसरे बच्चे के बाद पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता था। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत आता है और सभी नियोक्ताओं को समान रूप से लागू करना चाहिए।

निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के नियोक्ताओं को अब अपनी अवकाश नीतियों को इस अनुसार संशोधित करना होगा, और श्रम मंत्रालय से विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यह निर्णय विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली कई महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा, जहाँ मातृत्व अधिकारों की जागरूकता अभी भी कम है।

हाई कोर्ट ने सरकार को कार्यान्वयन की निगरानी करने और छह महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया, जिससे इस विस्तारित लाभ को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शिक्षा

हिमाचल राज्यपाल ने एसजेवीएन चित्रकला प्रतियोगिता में युवा कलाकारों को सम्मानित किया



हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हाल ही में कला के क्षेत्र में युवा प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। यह अवसर एसजेवीएन ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता 2026 था, जहाँ युवा कलाकारों ने ऊर्जा संरक्षण के विषय पर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। राज्यपाल, युवा कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण से प्रभावित होकर, उनके योगदान के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करने के लिए समय निकालते हैं।

राजनीति

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में स्थायी उच्च न्यायालय की मांग की



हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज धर्मशाला में स्थायी उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

यह प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य के पश्चिमी जिलों के निवासियों के लिए तेज़ न्यायिक पहुँच की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अस्थायी न्यायालय की क्षमता सीमित है और अक्सर मामलों के निपटारे में देरी होती है।

सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु यह मांग पहले भी स्थानीय नेताओं द्वारा की गई थी।

यह प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा, ताकि शहर में एक स्थायी न्यायिक सुविधा की स्थापना की संभावना पर विचार किया जा सके।

राजनीति

एमडी एचपीएमसी डी सी राणा ने नई दिल्ली में आईआईटीएफ के हिमाचल पवेलियन का दौरा किया



हिमाचल प्रदेश के मंत्री डी सी राणा ने आज नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में हिमाचल पवेलियन का दौरा किया। प्रगति मैदान में स्थित इस पवेलियन में राज्य के पर्यटन स्थल, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया।

एक प्रमुख मंच है जहाँ भारतीय राज्य और निजी कंपनियाँ व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती हैं। हिमाचल के पवेलियन में पहाड़ी पर्यटन, सेब की बाग़ीचे और पारंपरिक शिल्पों को उजागर किया गया, जिससे खरीदारों और यात्रियों का ध्यान आकर्षित हो सके।

राणा की उपस्थिति राज्य सरकार की इस तरह के राष्ट्रीय मेले का उपयोग आर्थिक प्रचार के लिए करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरे से बाजार संबंध मजबूत होंगे और हिमाचल के उत्पादों तथा पर्यटन स्थलों की दृश्यता बढ़ेगी।

पवेलियन मेले की अवधि तक खुला रहेगा, जिससे प्रतिनिधियों, पर्यटकों और व्यापारियों को हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट पेशकशों का पता लगाने का अवसर मिलेगा।

बिज़नेस

शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सभी बैंकों की छुट्टी – राष्ट्रीय अवकाश



इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि 21 नवंबर 2026, शनिवार को पूरे भारत में सभी नियत बैंकों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर इस दिन शाखा बंद रहने की पुष्टि की है।

लेन-देन जैसी रिटेल बैंकिंग सेवाएँ शाखाओं में उपलब्ध नहीं होंगी। ग्राहकों को एटीएम, डिजिटल बैंकिंग एप्लिकेशन और मोबाइल वॉलेट का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जब तक कि व्यक्तिगत बैंकों द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।

चेक क्लियरिंग, NEFT/RTGS जैसी रीयल-टाइम भुगतान और ऋण वितरण जैसी प्रक्रियाएँ अगले कार्यदिवस, यानी 23 नवंबर 2026, सोमवार को फिर से शुरू होंगी। व्यापारिक और व्यक्तिगत योजनाओं को इस अनुसार समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

RBI ने बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस, वेबसाइट और शाखा संकेतों के माध्यम से अवकाश की जानकारी देने की भी याद दिलाई है, ताकि भ्रम से बचा जा सके।

स्थानीय

सोलन में बुजुर्ग व्यक्ति पर वाहन का टक्कर, सीसीटीवी फुटेज सामने



हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर वाहन का टक्कर हुआ, जिसे पास के सीसीटीवी कैमरे ने दर्ज किया। स्थानीय मीडिया ने इस फुटेज को सार्वजनिक किया है।

आपातकालीन सेवाएँ तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में अभी तक कोई विवरण नहीं दिया गया है।

पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें वाहन की गति और ट्रैफ़िक नियमों के पालन की जांच शामिल है। सीसीटीवी क्लिप में टक्कर का क्षण और आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई देती है।

यह घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर करती है, जिससे ट्रैफ़िक नियमों की कड़ी प्रवर्तन और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपायों की मांग बढ़ रही है।

राजनीति

कांग्रेस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति से हिमाचल प्रदेश कोष में 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री सुखु



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखु सिंह सुख़ु ने कहा कि कांग्रेस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति ने राज्य के कोष में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह बयान उन्होंने हालिया प्रेस ब्रीफ़िंग में दिया, जिसमें उन्होंने दृढ़ शासन के माध्यम से वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने पर बल दिया।

के बाद लागू की गई नीतियों और राजस्व उपायों ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि यह राशि किन-किन स्रोतों से आई है, पर यह कहा कि अतिरिक्त फंड विकास परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि 4,000 करोड़ की इस बढ़ोतरी का असर हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे बजट वाले राज्य पर काफी महत्वपूर्ण होगा। यह बयान वर्तमान सरकार के वित्तीय उपलब्धियों को उजागर करता है।

सुखु ने नागरिकों से सहयोग की अपील की, ताकि यह अतिरिक्त संसाधन बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में सुधार के रूप में जनता तक पहुँच सके।